



Scan to Read in
Details

सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट पुलिस ने अनुमति देने से किया इनकार, कई ट्रेनें रद्द

57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की खबर, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने बनाए 10 डिटेंशन सेंटर, राजधानी में निगरानी बढ़ाई गई

एजेंसी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन कल होने की खबर के बीच पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। किसी भी अग्रिम स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया जा रहा है। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शन की तैयारियों से जुड़ी खबरों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन संभावित भीड़ और यातायात पर पड़ने वाले असर को लेकर सावधानी बरत रहा है। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की तैयारी

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद किए जाने की खबर भी सामने आई है। यदि इन स्टेशनों पर परिचालन रोक जाता है, तो इसका असर दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और दिल्ली आने वाले लोगों पर पड़ सकता है। मेट्रो राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का एक प्रमुख साधन है। बड़ी संख्या में स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों को दूसरे मार्गों और परिवहन के वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी होगा।

प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए

दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द होने की खबर

प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। खासकर दूसरे राज्यों से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति, प्रस्थान का समय और संभावित बदलावों की जानकारी रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें। ट्रेन रद्द होने या परिचालन में बदलाव की स्थिति में वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करना उपयोगी रहेगा।

के दौरान आवश्यक इंतजाम उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन किसी भी

आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से प्रभावित इलाकों में जाने से बचें और घर से निकलने से पहले यातायात संबंधी अपडेट प्राप्त करें। दिल्ली आने वाले यात्रियों को ट्रेन और मेट्रो सेवाओं की स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए। वहीं, राजधानी में रहने वाले लोगों को पुलिस और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिलहाल प्रदर्शन की अनुमति, ट्रेन रद्द होने और मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से संबंधित सभी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण है। यात्रियों को अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित विभागों की ताजा सूचना अवश्य देखनी चाहिए।

अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने पर जोर दे रहा है। हालांकि, डिटेंशन सेंटरों के इस्तेमाल, संबंधित स्थानों और अन्य विस्तृत व्यवस्थाओं के बारे में आधिकारिक पुष्टि के आधार पर ही जानकारी दी जानी चाहिए।

नोएडा एयरपोर्ट का नाम होगा 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान

● यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर नामकरण का फैसला चर्चा में

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नोएडा एयरपोर्ट का नाम 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' होगा। इस घोषणा के बाद प्रदेश में विकसित हो रहे इस महत्वाकांक्षी हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नोएडा एयरपोर्ट को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। एयरपोर्ट के आसपास होटल, परिवहन, वेयरहाउसिंग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सेवाओं से जुड़े निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक



लाभ एयरपोर्ट के परिचालन, यात्री संख्या और उससे जुड़ी औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार पर निर्भर करेगा। नोट: एयरपोर्ट के नामकरण की औपचारिक स्थिति और संबंधित सरकारी मंजूरी के बारे में अंतिम जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि की जानी चाहिए।

पश्चिमी यूपी को मिलेगा बेहतर हवाई संपर्क

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास दिल्ली-एनसीआर में हवाई यातायात का दबाव कम करने और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस परियोजना से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के पूरी तरह विकसित होने पर यात्रियों को हवाई यात्रा के अधिक विकल्प मिल सकते हैं। इसके साथ ही कारोबार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद एयरपोर्ट के नाम को लेकर जानकारी दी। नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। इसके विकास से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की घोषणा को प्रदेश की विमानन और आधारभूत संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के रूप में देखा जा रहा है।

‘ट्रेन और मेट्रो सेवाएं न हों पूरी तरह बंद’

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- ऐसा फैसला लें, जनता को न हो परेशानी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशन बंद करने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली के लिए ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेवाओं को नियंत्रित तरीके से जारी रखने को कहा कि ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल, सीईसी के खिलाफ सीजेपी और कुछ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन का एलान किया है। शुक्रवार को सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए रखने के फैसले पर पुनर्विचार करे और किसी अन्य स्थान को प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित करने पर उचित निर्णय ले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश



सूर्यकांत की पीठ को बताया कि सक्षम प्राधिकारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य स्थान को निर्धारित करने पर विचार करेगा। सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अदालत के आदेश में कहा गया, 'सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अब समय आ गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त किसी अन्य स्थान की पहचान कर उसे निर्धारित किया जाए। सक्षम प्राधिकारी इस सुझाव पर विचार करे और उचित निर्णय ले।' अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संशोधित पाबंदियों और संबंधित परामर्शों का समाचार पत्रों, आधिकारिक वेबसाइटों और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इससे यात्रियों को बेरिक्केडिंग, प्रतिबंधों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी मिल सकेगी।



मेरठ समेत 7 शहरों में ओले गिरे, लखनऊ में बाढ़

पार्क-मंदिर में पानी घुसा, गोंडा के 8 गांव जलमग्न, लखीमपुर में 13 घर नदी में समाए

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने कई जिलों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं ओलावृष्टि से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो कहीं भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मेरठ समेत सात शहरों में ओले गिरने की खबर है, जबकि राजधानी लखनऊ में जलभराव के कारण पार्कों और मंदिरों तक पानी पहुंच गया। दूसरी ओर, गोंडा में आठ गांवों के जलमग्न होने और लखीमपुर खीरी में नदी के कटान से 13 घरों के बह जाने की सूचना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली और ओलावृष्टि हुई। मेरठ समेत तीन शहरों में ओले गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम में आए इस बदलाव का असर आम जनजीवन के साथ खेती-किसानी पर भी पड़ने की आशंका है। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन संबंधित क्षेत्रों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर ही किया जा सकेगा। गोंडा जिले में बाढ़ के कारण स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। यहां आठ गांवों के जलमग्न होने की खबर है। गांवों में पानी भरने से ग्रामीणों के सामने



लखनऊ में जलभराव, पार्क और मंदिर तक पहुंचा पानी

राजधानी लखनऊ में बारिश और जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई स्थानों पर पानी भरने से सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुईं। पार्कों और मंदिरों तक पानी पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में जलभराव की स्थिति ने जलनिकासी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बारिश के दौरान पानी की निकासी प्रभावित होने से निचले इलाकों में स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में जलनिकासी और राहत संबंधी इंतजाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

आवागमन, दैनिक जरूरतों और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने जैसी समस्याएं पैदा हो

लखीमपुर खीरी में नदी के कटान से 13 घर बहे

लखीमपुर खीरी में नदी के कटान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कटान के कारण 13 घर नदी में समा गए। घरों के बह जाने से प्रभावित परिवारों के सामने रहने और घरेलू सामान की सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। नदी के किनारे बसे गांवों में कटान एक गंभीर समस्या बन सकता है। जलस्तर में वृद्धि और लगातार कटाव होने पर आसपास के घरों तथा जमीन को भी खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना आवश्यक है।

मौसम और बाढ़ ने बढ़ाई प्रशासन की चुनौती

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ओलावृष्टि, जलभराव, बाढ़ और नदी कटान की घटनाओं ने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। शहरी क्षेत्रों में जलनिकासी दुरुस्त रखना, जबकि ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए अहम है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन, राहत व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौसम की स्थिति और नदियों के जलस्तर पर निगरानी बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते कदम उठाए जा सकें।

अमरोहा में आधे घंटे तक हुई बारिश, ओले भी गिरे

अमरोहा में शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर होते-होते बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई और वातावरण सुहाना हो गया। करीब आधे घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा।

सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी जाती है। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने पहुंचने से पशुओं के लिए चारा, पेयजल और के लिए प्रशासनिक निगरानी और आवश्यक जरूरी सामान की उपलब्धता भी चुनौती बन सहायता की जरूरत है।

दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को यूपी सरकार की सौगात, मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। इस पर राज्य सरकार 2142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली के अवसर पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली के अवसर पर दिया जाएगा। योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े होंगे और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा। सरकार ने पात्रता के लिए यह शर्त निर्धारित की है। योगी सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में भी दीपावली और होली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराती रही है। अब चालू वित्तीय वर्ष में भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के अनुसार, इससे गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा और महिलाओं तथा बच्चों को परंपरागत ईंधन के धुएँ से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। वहीं, योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को एयरपोर्ट का नाम 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर' रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों के साथ पत्रकार वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि 65 लाख से अधिक



गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले। 3.67 करोड़ राशन कार्डधारक परिवारों के करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन से 2.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले। 3.37 करोड़ शौचालय और 59,183 सामुदायिक शौचालय बने। उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। होली और दीपावली पर राज्य सरकार मुफ्त सिलेंडर दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में छह करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हुए। इनसे 9.90 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवच मिला। 1.09 करोड़ गंभीर रोगियों को 18,798 करोड़ रुपये का मुफ्त उपचार मिला। आरोग्य मेलों में 14.67 करोड़ लोगों का उपचार हुआ। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स संचालित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 65 लाख नियुक्तियां हुईं। 31.11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और 62 लाख से अधिक को स्मार्टफोन तथा टैबलेट दिए गए। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, काशी में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। पीएम स्वनिधि से 15 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सहायता और स्वामित्व योजना से 1.10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घरौनी मिली। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिला।

मायावती ने कांशीराम को दी श्रद्धांजलि, भारत रत्न देने की मांग दोहराई

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बसपा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आकाश आनंद समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी कांशीराम को नमन किया। इस मौके पर मायावती ने उनके सामाजिक परिवर्तन से जुड़े योगदान को याद करते हुए बहुजन समाज के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज ही उनका असली परिवार है और उसका हित उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बसपा के संस्थापक कांशीराम ने बहुजन समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का जो मिशन शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। मायावती ने पार्टी और आंदोलन को परिवारवाद से मुक्त रखकर आगे बढ़ाने तथा बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ.



भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना ही बसपा का उद्देश्य है और वह कांशीराम के विश्वास को कभी आंच नहीं आने देंगे। इस अवसर पर मायावती ने केंद्र सरकार से एक बार फिर मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन में कांशीराम का योगदान ऐतिहासिक रहा है और उनके कार्यों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा की ओर से

देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मायावती ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के मामले में सरकारों को कारोबारी सोच के बजाय संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके मुताबिक, जनकल्याण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देकर ही आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।

त्योहारों से पहले इंडो-नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्त

अमृत उजाला संवाददाता

श्रावस्ती। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ओर से संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में मल्हीपुर पुलिस और एसएसबी की टीम ने तिकोनी मोड़ पर संयुक्त गश्त कर सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की तथा संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखने और सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त निगरानी से सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां

सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं, ताकि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। श्रावस्ती पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस इकाई या डायल 112 पर सूचना दें। त्योहारों से पहले सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी के तहत पुलिस और एसएसबी की टीमों सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था सभाल रही हैं।



लखनऊ में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर

होमगार्ड ने पत्नी और बेटी की गला घोटकर हत्या की, फिर खुद पुलिस को फोन कर किया सरेंडर

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया। कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र के भोला खेड़ा इलाके में एक होमगार्ड पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने का आरोप है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी और आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी होमगार्ड रविंद्र शंकर भोला खेड़ा इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी श्याम दुलारी (55) और बेटी पूजा (32) की हत्या की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों की गला घोटकर हत्या की गई। वारदात में मोबाइल की डाय केबल का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार तड़के हुई। आरोप है कि घर में सो रही पत्नी और बेटी को निशाना बनाया गया। इसके बाद आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका पूजा की पहली शादी वर्ष 2017 में हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। इसके बाद वर्ष 2022 में उसने दूसरी शादी की थी। बताया जाता है कि दूसरी शादी भी अधिक समय तक नहीं चल सकी और तलाक के बाद वह अपने मायके में रहने लगी थी। पुलिस परिवार की



घरेलू विवाद को माना जा रहा वजह

प्रारंभिक जांच में परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे विवाद को घटना की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसकी पत्नी तथा बेटी के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। कुछ समय पहले पत्नी के बिना बताए घर से चले जाने और बाद में लौट आने की घटना भी सामने आई है। इस मामले को लेकर परिवार में तनाव होने की बात कही जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले घर में किस बात को लेकर विवाद हुआ था और क्या इसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

परिस्थितियों, आपसी संबंधों और घटना से पहले हुए विवादों की जानकारी जुटा रही है। जांच अधिकारियों का प्रयास है कि सभी तथ्यों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर वारदात की पूरी कड़ी को स्पष्ट किया जा सके। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे

में हलचल मच गई। दक्षिणी जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से ज़रूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया



जांच के बाद सामने आएगी वारदात की पूरी सच्चाई

राजधानी में एक ही परिवार के दो सदस्यों की हत्या की इस घटना ने इलाके के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने कथित वारदात के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पृच्छाछा कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की आगे की जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।

है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पृच्छाछा के जरिए घटना के क्रम और उसके पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

संपादकीय नोट: खबर को उपलब्ध प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर विस्तार दिया गया है। हत्या के कारणों को अभी संभावित माना गया है; जांच के निष्कर्ष आने तक आरोपों को अंतिम तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायतों में चार महीने में 77 करोड़ खर्च, नए कार्यों के प्रस्ताव नहीं आए



अमृत उजाला संवाददाता

अयोध्या। जिले की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल के दौरान विकास निधि खर्च करने की रफ्तार चर्चा में है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार महीनों में पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की कुल करीब 78.40 करोड़ रुपये की धनराशि में से लगभग 77.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। तीन अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों के खातों में केवल 78.57 लाख रुपये शेष बताए गए हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि का 99.29 प्रतिशत और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का 98.41 प्रतिशत व्यय हो चुका है। जिले की 772 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए पूर्व प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी। नए विकास कार्य शुरू कराने के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन लेने की व्यवस्था है। हालांकि, चार महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद किसी भी ग्राम पंचायत

से नए कार्य का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में पुरानी कार्ययोजनाओं के अधूरे कार्यों पर ही उपलब्ध धनराशि खर्च की जा रही है। ग्राम पंचायतों में खर्च की जा रही धनराशि से हैंडपंप मरम्मत, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, रीबोर और परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं। नए कार्यों के प्रस्ताव नहीं आने के कारण विकास की नई योजनाएं शुरू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। वहीं, वित्त आयोग की धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च होने से ग्राम पंचायतों के खातों में उपलब्ध शेष राशि भी काफी कम रह गई है। जिला पंचायतराज अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि नए कार्यों के अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायतों से अब तक कोई आगणन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं। उनके अनुसार, प्रशासक प्राथमिकता के आधार पर पुरानी कार्ययोजना के शेष कार्यों को पूरा करा रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों में तेजी से हो रहे खर्च और नए कार्यों के प्रस्ताव नहीं आने की स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है।

मथुरा में पुलिस मुठभेड़, बाबरिया गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

अमृत उजाला संवाददाता

मथुरा। मथुरा से रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। मथुरा के थाना फरह क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बाबरिया गैंग के दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरह भेजा गया। पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 की रात मुखाबिर से सूचना मिली थी कि चोरी की घटनाओं में वांछित बाबरिया गैंग के दो सदस्य राजस्थान की ओर से फरह आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने परखम नहर पुल के पास चेकिंग शुरू कर दी। रात करीब 9 बजकर 42 मिनट पर ओल की तरफ से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि



संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और परखम गौशाला रोड की ओर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों घायल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ सुलील पुत्र भीमा और संजय पुत्र ऊदा के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान के दौसा जिले के गणेशपुरा के मूल निवासी बताए गए हैं और वर्तमान में मथुरा के थाना मगोरा क्षेत्र के पुरा

में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .315 बोर के दो तमचे, दो जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, चोरी की सफेद धातु की दो जोड़ी पायजेब और 10,700 रुपये बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी थाना फरह में दर्ज चोरी के एक मुकदमे में वांछित थे। फिलहाल, मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, चयनित स्थलों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन

श्रावस्ती। आगामी दुर्गा पूजा, महानवमी, दशहरा और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आठ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। डीएम ने सभी जनपदवासियों से त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दुर्गा पूजा पंडालों और मूर्ति विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। मूर्ति विसर्जन केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थलों पर ही कराया जाए। पूजा पंडालों में अश्लील गाने और डांस पर प्रतिबंध

का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्योहारों से पहले बिजली आपूर्ति, सड़कों, साफ-सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। धार्मिक स्थलों पर क्षमता से अधिक भीड़ एकत्र न होने देने के भी निर्देश दिए गए। वहीं, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने सभी क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा।



सड़क पर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा विपक्ष, रात 8 बजे द्रौपदी मुर्मू से होगी मुलाकात

→ एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इंडिया गठबंधन की चिंताएं
→ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करेंगे विपक्षी सांसद

एजेंसी

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मिल गया है। शुक्रवार, 9 अक्टूबर को रात आठ बजे विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में 10 सांसद शामिल होंगे। विपक्षी नेता इस मुलाकात के दौरान चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताएं रखेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए पहली बार 2 अक्टूबर को अनुरोध भेजा गया था। विपक्ष चाहता था कि इंडिया गठबंधन के 15 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिल सके, ताकि विभिन्न विपक्षी दलों के नेता अपनी बात रख सकें। हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति भवन की ओर से 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है। अंतिम सूची की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। विपक्षी गठबंधन राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करना चाहता है। इसके लिए विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की भी योजना बताई



एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल

विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटने और उनके मतदान के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक का नाम अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान विपक्षी सांसद इन मुद्दों को उठकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।

गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर,

छह अक्टूबर से जारी है विपक्ष का प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सांसद पिछले कई दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया था। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद 7 अक्टूबर को भी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 8 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर पहुंचकर विरोध कार्यक्रम किया। लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग विपक्ष की रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है।

राष्ट्रपति से मुलाकात पर टिकी नजरें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब स्टूटक्रो को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। इस मुलाकात के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्षी नेताओं की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और आगे की राजनीतिक रणनीति क्या रहती है।

चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया से संबंधित नियमों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखा जाना महत्वपूर्ण होगा।

मस्क के आरोपों पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है। उनका यह बयान सैटेलाइट संचार सेवाओं को लेकर जारी विवाद और एलन मस्क के आरोपों के बीच आया है। सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 के दौरान कहा, 'एक विशेष कंपनी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन तीन कंपनियों को सैटेल्स लाइसेंस मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाता राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही अपना परिचालन शुरू कर सकते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क का बचाव किए जाने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कहा कि उनकी पार्टी को यह भी नहीं पता कि वह 'बाएं' जा रही है या दाएं। सिंधिया ने कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि



भारत में 1.1 अरब ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं और देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में 5जी कवरेज उपलब्ध है। इससे पहले, संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा था कि भारत में सैटेलाइट संचार सेवाओं की शुरुआत फिलहाल गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि सभी सैटेलाइट संचार कंपनियां नियामकीय प्रक्रिया के लगभग समान चरण में हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से साइडलाइन में बातचीत में पेम्मासानी ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं को पहले ही लाइसेंस और स्पेक्ट्रम से संबंधित अस्थायी मंजूरियां जारी कर चुका है। हालांकि, परिचालन शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी आकलन पूरा किए जाने पर निर्भर है।

आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बीसी के 34 प्रतिशत आरक्षण पर याचिका खारिज

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा बीसी आरक्षण बढ़ाने के औचित्य हेतु प्रस्तुत आंकड़ों, विशेष रूप से एकीकृत परिवार सर्वेक्षण के निष्कर्षों के कानूनी आधार पर सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाई कोर्ट के पास आंकड़ों को अविश्वसनीय बताकर खारिज करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि, न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से यह साबित करने को कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानने में कहां गलती की है कि सर्वेक्षण के आंकड़े आरक्षण निर्धारण का आधार नहीं बन सकते। याचिका खारिज करने से पहले सुप्रीम



कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बड़े हुए आरक्षण को उचित ठहराने के लिए सर्वेक्षण आंकड़ों पर भरोसा करने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी (बहुसंख्यक वर्ग) के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले दो सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि यह कोटा कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकायों में सभी श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण

50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह फैसला चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करना 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए उसके प्रमुख वादों में से एक था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 अगस्त को बड़े हुए कोटे की घोषणा करते हुए कहा था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में बीसी समुदाय को 34 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को इस फैसले को चुनौती देने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को छह सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया। इसने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद ही चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

मनोरंजन

क्या जान्हवी कपूर अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में हैं? एक्ट्रेस की लेटेस्ट पोस्ट ने बढ़ाई अटकलें



मुंबई। जान्हवी कपूर जल्द ही ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रख सकती हैं। एक्ट्रेस की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पोस्ट में जान्हवी मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आ रही हैं। साथ ही, उनके हाथों में कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जान्हवी की इस पोस्ट ने फैस और ब्यूटी लवर्स का ध्यान खींचा है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, अभी तक जान्हवी या उनकी टीम की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पोस्ट में जिस तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप पर फोकस किया गया है, उसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हुई है, जब जान्हवी कपूर हाल ही में पेरिस फैशन वीक में अपनी मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में थीं। ग्लोबल फैशन मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर फैशन और ब्यूटी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक, जान्हवी लगातार सिनेमा से आगे अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं। अगर ये अटकलें सच साबित होती हैं, तो जान्हवी कपूर उन बॉलीवुड सितारों की सूची में शामिल हो जाएंगी, जिन्होंने ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में कदम रखा है।